Women Empowerment, Girl Child Safety, Legal Awareness, Rajasthan Governance.

Within the framework of the Pannadhay Suraksha evam Samman Kendra of the Department of Women Empowerment, a Jagruti Saptah is being celebrated in Jaipur district between 6-11 April to sensitize the girls on their rights, safety, and welfare. This campaign also involved awareness programmes in the Maharaja Government Girls Senior Secondary School, Chaura Rasta, and M.G.G.S. Vishisht N.V.D. Bal Mandir, Mahavir Marg, Jaipur. The efforts were aimed at legal awareness, child marriage prevention, self-reliance, self-defence, emergency response, and digital safety. This programme is significant in terms of RAS examination as it relates to women welfare, child protection laws, cyber awareness and institutional support systems at the state level.

The following are some of the major points of the Programme

- “Jagruti Saptah” is being organised from 6 to 11 April in Jaipur district.
- The programme is being implemented in the Pannadhay Suraksha evam Samman Kendra.
- It is under the management of the Department of Women Empowerment.
- Two schools of girls in Jaipur were used to carry out awareness campaigns.
- Girls were informed about the provisions of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
- The negative social and legal impacts of child marriage were described.

- There was a dissemination of information on different welfare programmes on women and girls.
- Students were also guided about the procedure for availing the benefits of these schemes.

Areas of Awareness Discussed.

The legal and social awareness is of a high quality.

- Girls were taught laws concerning women safety.
- They were made aware of the institutional support mechanisms to help them in protection and counselling.
- The programme raised awareness on rights, dignity and personal safety.
- Skill development and self reliance is another aspect that can be considered important performance standards.
- Counsellors motivated girls to be independent.
- Information was provided about skill development opportunities.
- Advice was provided on the issue of self-employment.

Safety, Health, and Emergency Preparedness

- Girls were educated on self-defence.
- They were trained on emergency safety measures.
- There was also the dissemination of basic knowledge about the first aid and life-saving services.

Electronic and cyber-security.

- Digital safety was discussed specially due to increasing cyber crimes.
- The programme raised awareness of the importance of being cautious in the internet.
- This renders the project timely in the face of increasing numbers of cyber attacks on women and children.

Significant Support Systems and Help Line Numbers are exchanged

- Women Safety and Advice Centre.
- One Stop Sakhi Centre.
- Child Helpline
- Emergency helpline numbers: 1098, 112, 1090, 181, and 1930

Significance for RAS Examination

- The programme is indicative of the concern of women empowerment and girl child protection in Rajasthan.

RASonly

- It points out how awareness campaigns can aid in the prevention of child marriage and enhance legal literacy.
- It applies to issues of women welfare schemes, social justice, child rights, cyber safety and state governance.

It also illustrates the connection between social empowerment and counselling, institutional support and emergency services.,

Conclusion

Jagruti Saptah is a significant awareness campaign that seeks to combine legal literacy, social protection, skill development with cyber safety among girls. The programme empowers the students by enabling greater awareness and empowerment at the grass-root level in Rajasthan through education on child marriage laws, welfare programs, self-defence and emergency assistance.

MCQs

1. Which was the centre of the organised Jaipur district Jagruti Saptah?

(a) Sakhi Suraksha Resource Centre.

(b) Pannadhay Suraksha evam Samman Kendra

(c) Rajiv Gandhi Women Welfare Centre

(d)Balika Nyay Sahayata Kendra

Answer: (b)

Explanation : The awareness programme was arranged under the Pannadhay Suraksha evam Samman Kendra which is operating under the Department of Women Empowerment. The campaign was to educate the girls on the issues of safety, rights, welfare programs, and legal provisions.

2. What was the specific law that was explained to the girls in the awareness programme?

(a) Protection of Children against Sexual Offences Act, 2012.

(b) Juvenile Justice Act, 2015

(c) Prohibition of Child Marriage Act, 2006

(d) Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Answer: (c)

RASonly

Explanation: The girls were made aware of the contents of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, during the programme. The negative effects of child marriage and the significance of legal awareness and social protection were also discussed during the session.

3. What was the number of the helplines that was provided during the programme to get emergency support?

(a) 1098

(b) 112

(c) 181

(d) All the above.

Answer: (d)

Explanation: The programme provided various numbers of emergency and support helplines such as 1098, 112, 1090, 181, and 1930. These figures were availed to enhance the awareness of girls concerning child protection, women safety, emergency help and cyber-help systems.

महिला सशक्तीकरण, बालिका सुरक्षा, विधिक जागरूकता, राजस्थान शासन

महिला अधिकारिता विभाग के पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र के अंतर्गत जयपुर जिले में 6 से 11 अप्रैल तक “जागृति सप्ताह” मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण के प्रति जागरूक बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत महाराजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा रास्ता तथा एम.जी.जी.एस. विशिष्ट एन.वी.डी. बाल मंदिर, महावीर मार्ग, जयपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विधिक जागरूकता, बाल विवाह की रोकथाम, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था। यह कार्यक्रम आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिला कल्याण, बाल संरक्षण कानूनों, साइबर जागरूकता तथा राज्य स्तरीय संस्थागत सहायता तंत्र से संबंधित है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- “जागृति सप्ताह” का आयोजन जयपुर जिले में 6 से 11 अप्रैल तक किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

RASonly

- इसका संचालन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- जयपुर के दो बालिका विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
- बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों को विस्तार से समझाया गया।
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
- छात्राओं को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

जागरूकता के प्रमुख क्षेत्र

विधिक और सामाजिक जागरूकता

- बालिकाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।
- उन्हें संरक्षण और परामर्श के लिए उपलब्ध संस्थागत सहायता तंत्र के बारे में बताया गया।
- कार्यक्रम के माध्यम से अधिकार, गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई।

कौशल विकास और आत्मनिर्भरता

- परामर्शदाताओं ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।
- कौशल विकास के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई।
- स्वरोजगार के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन तैयारी

- बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई।
- उन्हें आपातकालीन सुरक्षा उपायों के बारे में प्रशिक्षित किया गया।
- प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक सेवाओं की मूलभूत जानकारी भी साझा की गई।

डिजिटल और साइबर सुरक्षा

- बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई।
- कार्यक्रम में इंटरनेट के उपयोग के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- इस कारण यह पहल महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते साइबर खतरों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक बनती है।

साझा किए गए महत्वपूर्ण सहायता तंत्र और हेल्पलाइन नंबर

- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र
- वन स्टॉप सखी केन्द्र

RASonly

- चाइल्ड हेल्पलाइन
- आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर: 1098, 112, 1090, 181 और 1930

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

- यह कार्यक्रम राजस्थान में महिला सशक्तीकरण और बालिका संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह बताता है कि जागरूकता अभियान बाल विवाह की रोकथाम और विधिक साक्षरता को बढ़ाने में कैसे सहायक होते हैं।
- यह महिला कल्याण योजनाओं, सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों, साइबर सुरक्षा और राज्य शासन जैसे विषयों से संबंधित है।
- यह सामाजिक सशक्तीकरण, परामर्श, संस्थागत सहायता और आपातकालीन सेवाओं के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है।

निष्कर्ष

जागृति सप्ताह एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान है, जो बालिकाओं के बीच विधिक साक्षरता, सामाजिक संरक्षण, कौशल विकास और साइबर सुरक्षा को एक साथ जोड़ता है। बाल विवाह कानून, कल्याणकारी योजनाओं, आत्मरक्षा और आपातकालीन सहायता के बारे में जानकारी देकर यह कार्यक्रम राजस्थान में जमीनी स्तर पर जागरूकता और सशक्तीकरण दोनों को मजबूत करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जयपुर जिले में आयोजित "जागृति सप्ताह" किस केन्द्र के अंतर्गत संचालित किया गया?
(a) सखी सुरक्षा संसाधन केन्द्र
(b) पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र
(c) राजीव गांधी महिला कल्याण केन्द्र
(d) बालिका न्याय सहायता केन्द्र

उत्तर: (b)

व्याख्या: यह जागरूकता कार्यक्रम पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित होता है। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाना था।

---

2. जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को विशेष रूप से किस कानून की जानकारी दी गई?
(a) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
(b) किशोर न्याय अधिनियम, 2015
(c) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
(d) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

RASonly

उत्तर: (c)

व्याख्या: कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई और विधिक जागरूकता तथा सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझाया गया।

---

3. कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा हेल्पलाइन समूह साझा किया गया था?

(a) 1098
(b) 112
(c) 181
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: कार्यक्रम में 1098, 112, 1090, 181 और 1930 जैसे अनेक आपातकालीन एवं सहायता हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए। इनका उद्देश्य बालिकाओं को बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और साइबर सुरक्षा से संबंधित सहायता प्रणालियों के प्रति जागरूक बनाना था।

Agricultural Development, Farmer Welfare, Agri-Technology, Rajasthan Governance.

Global Rajasthan Agritech Meet 2026 is being framed as a significant platform to enhance farmer welfare, agricultural innovation, and policy dialogue in Rajasthan.

The event, to be hosted in Jaipur on 23-25 May, will bring together farmers, scientists, investors and policy-makers on one platform. The meet will create awareness on the current farming practices, international agricultural practices and government initiatives benefiting farmers. Since 15 April, publicity chariots will be dispatched at gram panchayat level to publicize welfare schemes and collect suggestions of the farmers. The plan is notable to the RAS test since it connects the fields of agriculture, irrigation, livestock support, encouragement of investments and state-led rural empowerment.

The essential characteristics of Global Rajasthan Agritech Meet 2026 are listed below.

- The event will take place at Jaipur between 23 and 25 May.
- It will give a shared platform to farmers, scientists, investors and policy-makers.
- The meet will enable farmers to learn on the new methods of farming and farming systems across the world.
- It will encourage debate on the welfare of farmers and agricultural empowerment.
- Publicity chariots will be dispatched at the gram panchayat level since 15 April.
- These chariots will create awareness of farmer welfare schemes.
- Suggestion boxes will also be put in place so that the farmers can give their feedback on schemes.
- The event will assist farmers to take advantage of the academic, institutional, and expert knowledge in the field of agriculture.

Objectives and Benefits

Objectives

- To make farmers more aware of modern and scientific methods of farming.
- To create a stronger agricultural ecosystem in Rajasthan.
- To promote communication among farmers with agricultural professionals of other origins.
- To advertise state programs relating to agriculture and rural well-being.
- To provide links between local farmers and world agricultural concepts and innovations.

Benefits

- Agricultural technologies and better production techniques will be exposed to farmers.
- The activity will be in favor of scientific agriculture and improved management of resources.

RASonly

- It will enhance the knowledge of irrigation, natural farming, crop safety, and water management.
- It will enhance access to policy support and welfare programs to farmers.
- The meet has the potential to augment future farm output and earnings opportunities in rural areas.

Scientific Farming and Sustainable Agriculture.

The Chief Minister emphasized that farmers must resort to scientific practices of farming and apply chemical manure in sparse form. He further suggested that cultivation should be done on the basis of soil testing in order to safeguard soil fertility in future. It also placed an emphasis on conservation of water with a special focus on the latest irrigation systems like sprinklers. This is an indication of the effort by the state to achieve sustainability and productivity.

The government has been supporting farmers and livestock sector.

- Rajasthan is a major producer of bajra, mustard, oilseeds, barley and guar.
- Moong and groundnut production is second in the state.
- It is third largest in production of soybean.
- Micro-irrigation systems have been set up on 4.80 lakh hectares in the state.
- 12,476 diggis have been built to store canal water.
- 32,918 kilometres of irrigation pipeline has been installed.
- Under the Chief Minister Mangla Pashu Bima Yojana more than 12 lakh animals have been covered under free insurance.
- By 1962 mobile veterinary services and 536 mobile vehicles, approximately 60 lakh animals have been treated benefiting over 15 lakh livestock owners.
- Under the Chief Minister Dugdh Utpadak Sambal Yojana, direct financial assistance of ₹5 per litre is being provided to milk producers.

Investment and Income Support Initiatives.

According to the state government, in the first year of its rule, the Rising Rajasthan Global Investment Summit resulted in 2,539 MoUs to invest in the agriculture sector worth over 43,000 crore. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is also providing ₹6,000 to farmers. Moreover, the state government has introduced the Chief Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, according to which the farmers receive an additional ₹3,000, which is to be raised to 12,000 in the future.

Significance to RAS Examination.

- The event is a significant one in the current affairs of agriculture and rural development.
- It also draws attention to the initiatives of Rajasthan in promoting agriculture and governance based on the farmer.

RASonly

- It applies to the subject of irrigation, livestock welfare, natural farming, investment, and agricultural policy.
- It also indicates the way the initiatives at the state level are being connected with contemporary technology and institutional backing.

Conclusion

The Global Rajasthan Agritech Meet 2026 is a significant project to transform agriculture and enhance the welfare of farmers in Rajasthan. Through technology, policy discourse, investment, irrigation support and livestock welfare, the event will strive to achieve a more robust agricultural ecosystem and enhance the long-term rural prosperity in the state.

MCQs

1. What will be the dates of Global Rajasthan Agritech Meet 2026 to be held in Jaipur?

(a) 15 to 17 April

(b) 20 to 22 May

(c) 23 to 25 May

(d) 1 to 3 June

Answer: (c)

Explanation : Global Rajasthan Agritech Meet 2026 will be organized in Jaipur between 23 and 25 May. It is a planned event aimed at uniting farmers, scientists, investors, and policy-makers, and promoting modern agriculture, farmer welfare, and agricultural innovation in Rajasthan.

2. What will be the action at the gram panchayat level to promote the welfare schemes of farmers since 15 April?

(a) There will be closed soil testing camps.

(b) Chariots of publicity will be despatched.

(c) There will be new crop taxes.

(d) Merging of milk cooperatives will be done.

Answer: (b)

Explanation: Since 15 April, publicity chariots will be dispatched to gram panchayat level to create awareness regarding the farmer welfare schemes. These chariots will

RASonly

also have suggestion boxes where farmers can express their opinions and suggestions on the implementation and benefits of different schemes.

3. Which of the statements given below are accurate with respect to the agricultural and farmer support practices by the state of Rajasthan as stated in the programme?

(a) Rajasthan is the biggest producer of soybeans.

(b) Over 12 lakh animals have received free insurance.

(c) Milk producers are being given ₹10 per litre under the support scheme

(d) It is the second largest producer of mustard.

Answer: (b)

Explanation : The programme emphasized how over 12 lakh animals have been insured free in the Chief Minister Mangla Pashu Bima Yojana. Rajasthan was reported to lead in crop like bajra and mustard, third in production of soybean and milk producers are not getting 10 per litre, but 5 per litre.

कृषि विकास, किसान कल्याण, कृषि प्रौद्योगिकी, राजस्थान शासन

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को राजस्थान में किसान कल्याण, कृषि नवाचार और नीतिगत संवाद को सशक्त करने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाला यह आयोजन किसानों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक ही मंच पर लाएगा। यह मीट आधुनिक खेती की पद्धतियों, वैश्विक कृषि प्रणालियों और किसानों के हित में संचालित सरकारी पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार रथ भेजे जाएंगे, जो कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और किसानों से सुझाव भी प्राप्त करेंगे। यह पहल आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, सिंचाई, पशुधन सहायता, निवेश प्रोत्साहन और राज्य-नेतृत्व वाले ग्रामीण सशक्तीकरण को एक साथ जोड़ती है।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- यह आयोजन जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होगा।
- यह किसानों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करेगा।
- यह मीट किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और विश्व की कृषि प्रणालियों को समझने में सहायता करेगी।
- यह किसान कल्याण और कृषि सशक्तीकरण पर संवाद को प्रोत्साहित करेगी।
- 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार रथ भेजे जाएंगे।

RASonly

- ये रथ किसान कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे।
- सुझाव पेटिकाएँ भी रखी जाएंगी, ताकि किसान योजनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।
- यह आयोजन किसानों को कृषि से संबंधित शैक्षणिक, संस्थागत और विशेषज्ञ ज्ञान का लाभ दिलाएगा।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- किसानों में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की विधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- राजस्थान में अधिक सुदृढ़ कृषि पारितंत्र का निर्माण करना।
- किसानों और विभिन्न पृष्ठभूमियों के कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।
- कृषि और ग्रामीण कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार करना।
- स्थानीय किसानों को वैश्विक कृषि विचारों और नवाचारों से जोड़ना।

लाभ

- किसानों को नई कृषि तकनीकों और बेहतर उत्पादन विधियों की जानकारी मिलेगी।
- यह आयोजन वैज्ञानिक खेती और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देगा।
- इससे सिंचाई, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
- यह किसानों की नीतिगत सहायता और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को मजबूत करेगा।
- यह मीट दीर्घकाल में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आय के अवसरों को बढ़ा सकती है।

वैज्ञानिक खेती और सतत कृषि

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती करनी चाहिए और रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि मृदा परीक्षण के आधार पर खेती अपनाई जाए, ताकि भविष्य के लिए भूमि की उर्वरता सुरक्षित रह सके। जल संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया और फव्वारा जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को अपनाने की बात कही गई। यह राज्य के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें उत्पादकता और सततता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

किसानों और पशुधन क्षेत्र के लिए सरकारी सहायता

- राजस्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार के उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
- राज्य मूंग और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- सोयाबीन के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है।
- राज्य में 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं।

RASonly

- नहरी जल के भंडारण के लिए 12,476 डिग्गियों का निर्माण किया गया है।
- कुल 32,918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज दिया गया है।
- 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं और 536 मोबाइल वाहनों के माध्यम से लगभग 60 लाख पशुओं का उपचार किया गया है, जिससे 15 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिला है।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है।

निवेश और आय सहायता संबंधी पहल

राज्य सरकार ने बताया कि अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में आयोजित राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु ₹43,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 2,539 समझौता ज्ञापन हुए। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ₹6,000 भी दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को ₹3,000 अतिरिक्त राशि दी जा रही है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर ₹12,000 करने का प्रस्ताव है।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

- यह आयोजन कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सामयिक घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- यह कृषि प्रौद्योगिकी संवर्धन और किसान-केंद्रित शासन के प्रति राजस्थान के प्रयासों को रेखांकित करता है।
- यह सिंचाई, पशुधन कल्याण, प्राकृतिक खेती, निवेश और कृषि नीति जैसे विषयों से संबंधित है।
- यह यह भी दर्शाता है कि राज्य स्तरीय पहलों को आधुनिक तकनीक और संस्थागत समर्थन से कैसे जोड़ा जा रहा है।

निष्कर्ष

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 राजस्थान में कृषि के आधुनिकीकरण और किसान कल्याण को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रौद्योगिकी, नीतिगत संवाद, निवेश, सिंचाई सहायता और पशुधन कल्याण को एक साथ जोड़कर यह आयोजन राज्य में अधिक मजबूत कृषि पारितंत्र विकसित करने और दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 जयपुर में किन तिथियों के दौरान आयोजित होने वाली है?
(a) 15 से 17 अप्रैल

RASonly

(b) 20 से 22 मई
(c) 23 से 25 मई
(d) 1 से 3 जून

उत्तर: (c)

व्याख्या: ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाना है, ताकि राजस्थान में आधुनिक कृषि, किसान कल्याण और कृषि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

---

2. 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कल्याण योजनाओं के प्रचार के लिए कौन-सा कदम उठाया जाएगा?
(a) मृदा परीक्षण शिविर बंद किए जाएंगे
(b) प्रचार-प्रसार रथ भेजे जाएंगे
(c) नई फसल कर व्यवस्था लागू की जाएगी
(d) दुग्ध सहकारी समितियों का विलय किया जाएगा

उत्तर: (b)

व्याख्या: 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान कल्याण योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु रथ भेजे जाएंगे। इन रथों में सुझाव पेटिकाएँ भी रखी जाएंगी, ताकि किसान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभ और सुधार से संबंधित अपने विचार और सुझाव भी दे सकें।

---

3. कार्यक्रम में उल्लिखित राजस्थान की कृषि एवं किसान सहायता व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है
(b) 12 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज दिया गया है
(c) दुग्ध उत्पादकों को सहायता योजना के अंतर्गत ₹10 प्रति लीटर दिए जा रहे हैं
(d) राज्य सरसों उत्पादन में दूसरे स्थान पर है

उत्तर: (b)

व्याख्या: कार्यक्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि राजस्थान बाजरा और सरसों जैसी फसलों में अग्रणी है, सोयाबीन में तृतीय स्थान पर है, और दुग्ध उत्पादकों को ₹10 नहीं बल्कि ₹5 प्रति लीटर की प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है

RASonly

Digital Infrastructure, Urban Governance, Smart City Initiatives, and Rajasthan Development.

The district of Ajmer has been the first free Wi-Fi zone in the state of Rajasthan, and it is an important move towards digital urban development in the state. On 10 April, Urban Development and Autonomous Governance Minister Jhabar Singh Kharra opened and laid foundation stone to crores of rupees worth development works at a programme held at the Kekri Municipality campus. The free internet service of 24-hour has been announced as a proactive move in the digital era of transformation and artificial intelligence. The project will be beneficial to students, youth, traders and the general public. The development is significant in the context of the RAS examination as it connects the digital governance, urban infrastructure, delivery of public services, and model city planning in Rajasthan.

The important aspects of the Initiative include:

- Kekri is declared the first free Wi-Fi area at Rajasthan.
- The free 24-hour internet provision has been made accessible to citizens.
- The announcement was done in a programme at the Kekri Municipality campus, Ajmer district.
- It also involved the opening of various development projects and laying the foundation of such projects.
- The state government has termed the initiative as a visionary move in the digital revolution and artificial intelligence era.
- The project will focus on enhancing digital as well as physical infrastructure in Kekri.

- According to the minister Kekri will become a model city in digital and civic facilities.

Characteristics of the Free Wi-Fi Project

- Free Wi-Fi is a project that has been established with an approximate cost of ₹3 crore.
- There are installed Wi-Fi routers in several large common locations in the city.
- More than 5,000 people can connect to the internet at one time through this facility.
- The citizens are being offered free internet service of approximately 5 Mbps.
- The internet facility will be available when there is bad weather.
- The system will last 3 years in the concerned company.
- Kekri is the first city in Rajasthan to get such a free Wi-Fi facility.

Development Works inaugurated and declared.

A number of development projects were launched and initiated under the Chief Minister Jan Awas Yojana. These include:

- Approach road and CC road construction
- Ajmer Road Welcome Gate Welcome Gate of Shri Ram
- Ward No. 38- Drain and CC road construction.
- Boundary wall: The proposed bus depot on the land of a municipal council.
- Baghera Road construction of the CC road in the colony.
- Take the approach road, Kadera Road to the FSTP plant.

Significance of the Initiative.

Digital Importance

- The project increases digital accessibility in an urban locality.
- It indicates the increased significance of internet connectivity in governance and in the day-to-day life.
- It may be used to facilitate learning, commerce, communication, and online inclusion.

Urban Development Importance

- The initiative integrates digital service delivery, as well as civic infrastructure development.
- It indicates a concentration on balanced urban development by the state government.
- It creates Kekri as a model town that could be used in digital urban projects in the future in Rajasthan.

RASonly

Relevance in RAS Examination.

- Significant in the contemporary matters of the urban development in Rajasthan.
- Applicable to the e-governance, smart cities, digital inclusion, and local self-government.
- Also important to learn how technology is being incorporated into the municipal public infrastructure.

Conclusion

The Kekri declaration on the first free Wi-Fi zone in Rajasthan is a remarkable move in the domain of digital governance and urban modernisation. Together with several civic infrastructural projects, the project accentuates the endeavour of the state to develop digitally empowered and even more connected urban centres. It can be used as an example of other towns in Rajasthan to develop similarly.

MCQs

1. Kekri, in the news recently, is the first free Wi-Fi zone of what state?

(a) Gujarat

(b) Rajasthan

(c) Madhya Pradesh

(d) Haryana

Answer: (b)

Explanation: Kekri, which is situated in Ajmer district, has been proclaimed to be the first free Wi-Fi zone in Rajasthan. The importance of this development is that it is indicative of increasing focus on digital infrastructure, access to the public internet, and urban development based on technology in the state.

2. What do you think the cost of the free Wi-Fi project created in Kekri will be?

(a) About ₹1 crore

(b) About ₹2 crore

(c) About ₹3 crore

(d) About ₹5 crore

Answer: (c)

RASonly

Explanation : The free Wi-Fi initiative in Kekri is created at a cost of approximately 3Crore. The project involves installing Wi-Fi routers at strategic strategic locations, free internet services and servicing of the services over a 3-year period.

3.Which of the following are accurate about the free Wi-Fi facility in Kekri?

(a) It offers 20 Mbps free internet service.

(b) It can connect around 500 users at one time

(c) The facility will last 1 year only.

(d) More than 5,000 people can connect at one time

Answer: (d)

Explanation: The Kekri free Wi-Fi can serve over 5,000 people simultaneously and offers approximately 5 Mbps free internet connectivity. The system will be in continuous operation during any weather conditions and the company concerned will maintain the system within 3 years.

डिजिटल आधारभूत संरचना, नगरीय शासन, स्मार्ट शहर पहल, राजस्थान विकास

अजमेर जिले का केकड़ी राजस्थान का पहला निःशुल्क इंटरनेट क्षेत्र बन गया है, जो राज्य में डिजिटल नगरीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 10 अप्रैल को केकड़ी नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सेवा की घोषणा को डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में एक दूरदर्शी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना से विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों और आमजन को लाभ मिलने की अपेक्षा है। आरएएस परीक्षा की दृष्टि से यह विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह डिजिटल शासन, नगरीय आधारभूत संरचना, लोकसेवा वितरण और आदर्श नगर योजना से जुड़ा है।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

- केकड़ी को राजस्थान का पहला निःशुल्क इंटरनेट क्षेत्र घोषित किया गया है।
- नागरिकों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- यह घोषणा अजमेर जिले के केकड़ी नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में की गई।
- कार्यक्रम में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।
- राज्य सरकार ने इस पहल को डिजिटल क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग का दूरदर्शी कदम बताया।

RASonly

- यह परियोजना केकड़ी की डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- मंत्री ने कहा कि केकड़ी डिजिटल और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में एक आदर्श नगर के रूप में विकसित होगा।

निःशुल्क इंटरनेट परियोजना की विशेषताएँ

- यह परियोजना लगभग ₹3 करोड़ की लागत से विकसित की गई है।
- शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर इंटरनेट राउटर लगाए गए हैं।
- इस सुविधा के माध्यम से एक समय में 5,000 से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं।
- नागरिकों को लगभग 5 एमबीपीएस की निःशुल्क इंटरनेट सेवा दी जा रही है।
- यह सुविधा हर मौसम में उपलब्ध रहेगी।
- संबंधित कंपनी 3 वर्ष तक इसका रखरखाव करेगी।
- केकड़ी राजस्थान का पहला शहर बन गया है, जहाँ ऐसी निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

लोकार्पित और घोषित विकास कार्य

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें शामिल हैं:

- अप्रोच रोड और सीसी सड़क निर्माण
- अजमेर रोड पर श्रीराम स्वागत द्वार
- वार्ड संख्या 38 में नाली और सीसी सड़क निर्माण
- नगर परिषद भूमि पर प्रस्तावित बस डिपो की चारदीवारी
- बघेरा रोड स्थित कॉलोनी में सीसी सड़क निर्माण
- कादेड़ा रोड से एफएसटीपी संयंत्र तक अप्रोच रोड निर्माण

पहल का महत्त्व

डिजिटल महत्त्व

- इस परियोजना से नगरीय क्षेत्र में डिजिटल पहुँच का विस्तार हुआ है।
- यह शासन और दैनिक जीवन में इंटरनेट संपर्क के बढ़ते महत्त्व को दर्शाती है।
- इससे शिक्षा, व्यापार, संचार और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है।

नगरीय विकास का महत्त्व

- यह पहल डिजिटल सेवा वितरण और नागरिक आधारभूत संरचना विकास को एक साथ जोड़ती है।

RASonly

- यह राज्य सरकार के संतुलित नगरीय विकास के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- इससे केकड़ी राजस्थान में भविष्य की डिजिटल नगरीय पहलों के लिए एक आदर्श नगर के रूप में उभर सकता है।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

- राजस्थान के नगरीय विकास से संबंधित सामयिक घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण।
- ई-शासन, स्मार्ट शहर, डिजिटल समावेशन और स्थानीय स्वशासन जैसे विषयों से संबंधित।
- यह समझने के लिए भी महत्वपूर्ण कि नगर स्तर पर लोक आधारभूत संरचना में प्रौद्योगिकी को कैसे जोड़ा जा रहा है।

निष्कर्ष

केकड़ी को राजस्थान का पहला निःशुल्क इंटरनेट क्षेत्र घोषित किया जाना डिजिटल शासन और नगरीय आधुनिकीकरण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम है। अनेक नागरिक आधारभूत संरचना कार्यों के साथ मिलकर यह पहल राज्य के डिजिटल रूप से सशक्त और बेहतर जुड़े हुए नगरीय केन्द्रों के निर्माण के प्रयास को दर्शाती है। यह राजस्थान के अन्य नगरों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बन सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हाल ही में समाचारों में रहा केकड़ी किस राज्य का पहला निःशुल्क इंटरनेट क्षेत्र बना है?
(a) गुजरात
(b) राजस्थान
(c) मध्य प्रदेश
(d) हरियाणा

उत्तर: (b)

व्याख्या: अजमेर जिले में स्थित केकड़ी को राजस्थान का पहला निःशुल्क इंटरनेट क्षेत्र घोषित किया गया है। यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य में डिजिटल आधारभूत संरचना, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच और प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय विकास पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।

---

2. केकड़ी में विकसित निःशुल्क इंटरनेट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?
(a) लगभग ₹1 करोड़
(b) लगभग ₹2 करोड़
(c) लगभग ₹3 करोड़
(d) लगभग ₹5 करोड़

उत्तर: (c)

RASonly

व्याख्या: केकड़ी की निःशुल्क इंटरनेट परियोजना लगभग ₹3 करोड़ की लागत से विकसित की गई है। इस परियोजना में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर राउटर स्थापित किए गए हैं, नागरिकों को निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है, और 3 वर्ष तक रखरखाव की व्यवस्था भी की गई है।

---

3. केकड़ी की निःशुल्क इंटरनेट सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) यह 20 एमबीपीएस की निःशुल्क इंटरनेट सेवा देती है
(b) इससे एक समय में लगभग 500 लोग जुड़ सकते हैं
(c) इस सुविधा का रखरखाव केवल 1 वर्ष तक किया जाएगा
(d) इससे एक समय में 5,000 से अधिक लोग जुड़ सकते हैं

उत्तर: (d)

व्याख्या: केकड़ी की निःशुल्क इंटरनेट सुविधा के माध्यम से एक समय में 5,000 से अधिक लोग जुड़ सकते हैं और लगभग 5 एमबीपीएस की निःशुल्क इंटरनेट सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा हर मौसम में उपलब्ध रहेगी तथा संबंधित कंपनी 3 वर्ष तक इसका रखरखाव करेगी।

RASonly

Women Reservation, Political participation, social welfare, Rajasthan Governance.

Chief Minister Bhajanlal Sharma asserted that a vision of a developed India with Prime Minister Narendra Modi in command is centred on women. In his speech on the Nari Shakti Vandan Programme in the Chief Minister residence, Jaipur, 10 April, he mentioned that 33 percent reservation of women in the Lok Sabha and State Assemblies has been opened through the Nari Shakti Vandan Adhiniyam which will enable women to participate more in politics. He also mentioned that the two-engine government has associated women empowerment with all aspects of life. The programme is important for the RAS examination because it is related to women reservation, political representation, welfare schemes, health, nutrition, entrepreneurship, and youth employment.

The main characteristics of the Programme

- The programme was held in the residence of the Chief Minister at Jaipur.
- Chief Minister said that Women are the core of vision of a developed India.
- He mentioned that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam has opened the way of 33 percent reservation to women in the Lok Sabha and State Assemblies.
- The action will result in more women being involved in politics.
- Chief Minister said that the government is helping women to realize their dreams.
- He also associated women empowerment with values of the Sanatan culture and the place of women in the development of the nation and state.

Government Efforts towards Women Empowerment.

Economic Empowerment

- Since 2014, a number of initiatives have been encouraged to empower women financially.
- Some of these are the Pradhan Mantri Mudra Yojana, Jan Dhan Yojana, Stand-Up India Yojana, Women Self-Help Groups, Namo Drone Didi Yojana, and Lakhpati Didi Yojana.
- Almost 20 lakh women in the state have been trained under the Lakhpati Didi Yojana.
- Over 16 lakh women have been inducted in Lakhpati Didi category.
- The Beti Bachao Beti Padhao was also mentioned as one of the significant initiatives towards women empowerment.

Basic Services, Housing, and Dignity.

- Under Pradhan Mantri Awas Yojana, allotment of houses is done in the name of women.
- Free LPG connections have been given under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.
- The Swachh Bharat Mission has served to make sure that women have their dignity by building toilets.
- Drinking water provision via Har Ghar Nal Se Jal program was also brought to the limelight.

Women and Healthy Tweez.

According to the Chief Minister, the government is paying special attention to the health and nutrition of women. Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, pregnant and lactating women receive assistance of ₹5,000 from the central government. This has been raised by the state government to ₹6,500. Under this scheme, 11 lakh 58 thousand pregnant women in the state have got ₹576 crore. In addition, he claimed that the Maa Voucher yojana is offering free sonography services to pregnant women. Other current programs are PM Poshan Yojana, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, Mission Indradhanush and Saksham Anganwadi Yojana.

HPV Vaccine Programme and Womens Health Protection.

- The programme was also alluding to the recent introduction of HPV vaccine campaign by Prime Minister Narendra Modi of Ajmer. This program was termed as a milestone to the safeguarding of young female in the state against severe health conditions like cervical cancer.
- After-tax subsidies on entrepreneurship and the creation of job opportunities among young people will be provided.

RASonly

Entrepreneurship and Self-Employment

- On entrepreneurship, the Chief Minister mentioned that the state government has implemented a Youth Policy to encourage it.
- Interest-free loans are being offered under the Chief Minister Yuva Swarozgar Yojana.
- The goal is to ensure that the young people are not only motivated to take up employment, but they should also be motivated to be job creators.

Employment Targets

- The government is targeting to create 4 lakh government jobs and 6 lakh private sector jobs.
- Over 1 lakh 25 thousand appointments are already done.
- Recruitment to 1 lakh 25 thousand new government jobs has also been paved the way.
- The Chief Minister also said that during the present government's tenure, not a single paper leak has taken place.

Value to RAS Examination.

- Relevant to the issues of women reservation and political participation.
- Applicable to the women empowerment schemes and social welfare policies.
- Important to questions on health, nutrition, entrepreneurship, and youth employment.
- Also helpful to learn about the relationship between the central and state welfare programs.

Conclusion

Nari Shakti Vandan Programme was used to underscore the increasing position of women in politics, development, health and economic empowerment. By connecting with the reservation, welfare schemes, maternal health, entrepreneurship and employment provision, the programme introduced women as the driving force of vision of a developed India and an empowered Rajasthan.

MCQs

1. What is the percentage of reservation of women in the Lok Sabha and State Assemblies?

(a) 25 percent

(b) 30 percent

(c) 33 percent

RASonly

(d) 50 percent

Answer: (c)

Explanation: According to the Chief Minister, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam has paved the path to 33 percent women reservation in Lok Sabha and State Assemblies. This will enhance the participation of women in politics and improve their position in governance and making decisions of the people.

2. Which of the following has been emphasized in the programme under the state under Lakhpati Didi Yojana?

(a) 10 lakh women trained and 8 lakh as Lakhpati Didis.

(b) 20 lakh women trained and over 16 lakh Lakhpati Didi.

(c) 16 lakh women trained and 20 lakh Lakhpati Didis.

(d) 11 lakh women trained and 5 lakh as Lakhpati Didis.

Answer: (b)

Explanation The programme emphasized that approximately 20 lakh women in the state are trained as per the Lakhpati Didi Yojana and over 16 lakh women have been inducted into the Lakhpati Didi category. This was introduced as a significant case of economic empowerment of women.

3. How much is being given under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana? It has been raised by the state government?

(a) ₹5,000

(b) ₹5,500

(c) ₹6,000

(d) ₹6,500

Answer: (d)

Explanation: According to the programme, the central government will be providing 5,000 to pregnant and lactating women under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, and the state government has raised this sum to 6,500. This is an indication of the attention the government gives to health and nutrition of women.

RASonly

महिला आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक कल्याण, राजस्थान शासन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना के केंद्र में महिलाएँ हैं। 10 अप्रैल को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने महिला सशक्तीकरण को जीवन के प्रत्येक पक्ष से जोड़ा है। यह कार्यक्रम आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महिला आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, पोषण, उद्यमिता और युवा रोजगार जैसे विषयों से संबंधित है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- कार्यक्रम का आयोजन जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना के केंद्र में महिलाएँ हैं।
- उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग खोला है।
- इस व्यवस्था से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने में सहयोग दे रही है।
- उन्होंने महिला सशक्तीकरण को सनातन संस्कृति के मूल्यों तथा राष्ट्र और राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका से भी जोड़ा।

महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी पहल

आर्थिक सशक्तीकरण

- वर्ष 2014 के बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाओं को बढ़ावा दिया गया।
- इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी योजना शामिल हैं।
- लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में शामिल किया गया है।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को भी महिला सशक्तीकरण की महत्वपूर्ण पहल के रूप में रेखांकित किया गया।

RASonly

आवास, गरिमा और मूलभूत सेवाएँ

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का आवंटन महिलाओं के नाम पर किया जाता है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के माध्यम से महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है।
- हर घर नल से जल पहल के माध्यम से पेयजल उपलब्धता को भी महत्व दिया गया।

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से ₹5,000 की सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर ₹6,500 कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 11 लाख 58 हजार गर्भवती महिलाओं को ₹576 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मा वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य संचालित योजनाओं में पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष और सक्षम आंगनबाड़ी योजना शामिल हैं।

एचपीवी टीकाकरण अभियान और महिला स्वास्थ्य सुरक्षा

कार्यक्रम में अजमेर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान का भी उल्लेख किया गया। इसे राज्य की युवतियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

युवा नीति और उद्यमिता को प्रोत्साहन

उद्यमिता और स्व-रोजगार

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा नीति लागू की है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- उद्देश्य यह है कि युवा केवल रोजगार प्राप्त करने वाले न बनें, बल्कि रोजगार देने वाले भी बनें।

रोजगार लक्ष्य

- सरकार 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र के रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है।
- अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं।
- 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है।

RASonly

- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्त्व

- महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
- महिला सशक्तीकरण योजनाओं और सामाजिक कल्याण नीतियों से संबंधित।
- स्वास्थ्य, पोषण, उद्यमिता और युवा रोजगार से जुड़े प्रश्नों के लिए उपयोगी।
- केंद्र और राज्य की कल्याणकारी पहलों के पारस्परिक संबंध को समझने में भी सहायक।

निष्कर्ष

नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ने राजनीति, विकास, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। आरक्षण, कल्याणकारी योजनाएँ, मातृ स्वास्थ्य, उद्यमिता और रोजगार सहायता को एक साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम ने महिलाओं को विकसित भारत और सशक्त राजस्थान की दृष्टि की एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है?
(a) 25 प्रतिशत
(b) 30 प्रतिशत
(c) 33 प्रतिशत
(d) 50 प्रतिशत

उत्तर: (c)

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और शासन तथा सार्वजनिक निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका अधिक मजबूत होगी।

---

2. राज्य में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में किस उपलब्धि को रेखांकित किया गया?
(a) 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण और 8 लाख को लखपति दीदी श्रेणी
(b) 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण और 16 लाख से अधिक को लखपति दीदी श्रेणी
(c) 16 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण और 20 लाख को लखपति दीदी श्रेणी
(d) 11 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण और 5 लाख को लखपति दीदी श्रेणी

उत्तर: (b)

व्याख्या: कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में

RASonly

शामिल किया गया है। इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया।

---

3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राशि बढ़ाने के बाद कुल कितनी सहायता दी जा रही है?

(a) ₹5,000
(b) ₹5,500
(c) ₹6,000
(d) ₹6,500

उत्तर: (d)

व्याख्या: कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹5,000 देती है, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर ₹6,500 कर दिया है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति सरकार की विशेष प्राथमिकता को दर्शाता है।

RASonly